

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/23/2024-2025

28 अगस्त, 2024

सेवा में,

श्री रागेश किसनराव निमकर
घर न. 1376/1, सुंदरम अपार्टमेंट,
चौधरी कम्पाउण्ड, कामतघर
भिवंडी, जिला-ठाणे-421302

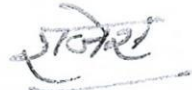
विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 12.08.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 20.08.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 5+5=10 रुपये का पो.आ.सं. 63सी 820981, 63सी 820982 संलग्न कर, बिन्दुवार जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।



(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

rticell-vps@nic.in

SPEED POST
4/9/24



Save Earth And Environment

RTI-24

VPS EC-SS/RTI-24/2024

DSR/1634

-2024 22.08.24

केंद्रीय सूचना के अधिकार 2005 के तहत सूचना के लिए आवेदन का प्रारूप



प्रति,

मा. सूचना अधिकारी

उपराष्ट्रपती कार्यालय, 6, मौलाना आझाद रोड,
नई दिल्ली-110002

1) अभ्यर्थी का नाम

:- नागेश किसनराव निमकर

2) पूरा पत्ता व दूरभाष नं.

:- घर नं.: 1376/1, सुंदरम अपार्टमेंट, चौधरी कम्पाउंड, कामतघर,
भिवंडी, जि. ठाणे. मो. : 9320899955

E-mail : dynamicactivity1@gmail.com

3) वांछित सूचना का उल्लेख (Subject)

- :- 1) भारत सरकार केंद्र सरकारके सन मार्च 2023 से 1 एप्रिल 2024 तक पुरे देशसे अलग अलग टॉक्स से भारत सरकारको कुल कितना रेवेन्यु जमा हुआ है, उसकी जानकारी दें।
2) भारत सरकारने सन 2024-25 के लिए खर्चवाला बजेट जो कि, भारत सरकार के प्रशासन पर कितना खर्चा होता है, उसमें संरक्षण (थळसेना / वायुसेना / नौसेना) तथा भारत सरकारके विभिन्न आस्थापना प्रशासन पर कुल रेवेन्युसे मिलनेवाले पैसोंमें कितना पर्संट खर्च होता है, इसकी जानकारी दें।
3) भारत सरकार पर 12 अगस्त 2024 तक कुल मिलाकर कितना ऋण है, (विदेशी कर्जा और स्वदेशी कर्ज) इसकी जानकारी दें।
4) भारत सरकार ने लिए हुये ऋणपर सालाना कितना ब्याज देना पड रहा है, इसकी जानकारी दें और केंद्रके रिजर्व बैंक में सरकारी डिपॉझीट दस लाख करोड रुपये पडे थे अब उसमें कितनी वृद्धी हुई है या कम हुये है (जो आनीबानी इमर्जेन्सी के लिए रखे है) इसकी जानकारी दें।
5) सन 2014 से आजतक केंद्र सरकारके विदेश मंत्रालयने मंत्रीयोंके विदेश दौरेपर अबतक कितना खर्च हुआ इसका ब्यौरा संक्षिप्त लिखत दें।

4) अदा किये गये शुल्क का उल्लेख

:- पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये

5) आवश्यक सूचना का वर्णन

:- उपरी सूचना के रूप में

6) सूचना टपालद्वारे अथवा व्यक्तिश

:- टपालद्वारे

7) अभ्यर्थी गरिबीरेखासे निचे

:-

परिवार का सदस्य है (बिपीएल प्रमाणपत्र)

8) सूचना का प्रयोजन

:- टपाल जानकारी के लिए

9) भारतीय नागरीक है

:- मैं एक भारतीय नागरीक हूं,

कृपया मांगी गई जानकारी अतिशिघ्र उपलब्ध कराये।

पत्ता :-

दिनांक : 12/8/2024

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

Thanks a Lot



22/08/2024

RTI

50/22

संख्या सं. सी. 221

20/-

REGISTERED No. D-111
नॉटरी क्रमांक सी-221



महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ
नवीन प्रशासन भवन, तळमज्जा
सभासपासमोर, मुंबई ४०० ०३२

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भारत राजपत्र

असाधारण
EXTRAORDINARY

असाधारण
भाग 12 अनुभाग 1
Part XII Section 1
भाग यात अनुभाग 1

प्रतिष्ठापक से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्रतिष्ठापक से प्रकाशित

सं. 1]	नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005/1 पौष (शके) 1927	[पृष्ठ 14
No. 1]	NEW DELHI, 22nd December 2005/1 Pousa (SAKA) 1927	[Vol. 14
अंक 1]	नवी दिल्ली, २२ दिसंबर २००५/१ पौष (शके) १९२७	[पृष्ठ १४

स्वतंत्र संकलन पणून फाईल करण्यारावी या भागाता नेगळे पृष्ठ प्रकाशित दिले आहेत.

सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करानेपर...!

- ★ अनुचित जानकारी देने से इनकार।
- ★ जानबुझकर आंशिक या भ्रामक जानकारी देने पर।
- ★ यदि जानकारी हटा दी जाती है अथवा नष्ट की जाती है।
- ★ यदि जानकारी में किसी भी तरह से हस्तक्षेप किये जानेपर।

सूचना अधिकारी आयुक्त सूचना अधिकारी को रुपये २५०/- प्रति दिन जैसे २५०००/- रु. तक अधिकतम जुर्माना लगा सकते हैं। साथ ही यदि कोई सूचना अधिकारी बार-बार इस प्रकार से सूचना उपलब्ध कराने में विफल रहता है या सूचना निर्देशकों का सक्ती से पालन न करनेपर उसके विरुद्ध विभागदार कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है।

- १) लोकसूचना अधिकारी (आरटीआय आवेदन)
- २) प्रथम सूचना अपीलीय अधिकारी (लोकसूचना अधिकारी सूचना न देनेपर इन्हें अपील करें)
- ३) द्वितीय सूचना अपीलीय अधिकारी (लोकसूचना अधिकारी और प्रथम सूचना अपीलीय अधिकारी इनके खिलाफ यहाँ अपील करें।)

(सूचना आयोग)